भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1878

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की राष्ट्रव्यापी शुरुआत

†1878. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा परिकल्पित भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) पहल के घटक, डिज़ाइन संरचना और कार्यात्मक चरण क्या हैं और इसके मुख्य अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने आईईएस के अवधारणा-सिद्ध कार्यान्वयन के लिए पायलट उपयोगिताओं का चयन किया है और यदि हाँ, तो ऐसी उपयोगिताओं के नाम और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आईईएस की राष्ट्रव्यापी शुरुआत के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और प्रमुख लक्ष्य क्या है;

(घ) आईईएस के विकास, परीक्षण और शुरुआत के लिए अब तक कितना बजट आवंटित किया गया है और कितना व्यय हुआ है; और

(ङ) अंतर-संचालन सुनिश्चित करने और दोहराव, विखंडन या तकनीकी रूप से अलग-थलग पड़ने से बचने के लिए जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम की मौजूदा परिचालन प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को आईईएस के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए सार्वभौमिक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाने के लिए भारतीय ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की परिकल्पना की गई ताकि विद्युत प्रणाली के अलग-अलग हिस्से मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित रूप से जुड़ सकें और संचार कर सकें। मंत्रालय ने आईईएस के घटक और डिजाइन सहित इसके रोडमैप के लिए मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों, जेनकोस, ट्रांसकोज आदि के प्रतिनिधियों सहित डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। आईईएस का उद्देश्य एक मानकीकृत मंच बनाना है जो आंकडों, सेवाओं और प्रणालियों को विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में निर्बाध रूप से एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाएगा।

दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मुंबई की वितरण यूटिलिटी की पहचान पायलट कार्यान्वयन के लिए की गई है और इसके प्रदर्शन की समय सीमा वित्त वर्ष 2026-27 है। आईईएस के विकास के लिए आवंटित निधि 51.3 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

****